The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-1, April-2023
www.theresearchdialogue.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

डा0 राजेश वर्मा

एम0एड0 विभागाध्यक्ष
शिक्षा संकाय
श्री पी0एल0 मेमोरियल पी0जी0 कॉलेज, बाराबंकी (उ0प्र0)

प्रेम चन्द्र वर्मा

एम0एड0 शोधकर्ता छात्र
शिक्षा संकाय
श्री पी0एल0 मेमोरियल पी0जी0 कॉलेज, बाराबंकी (उ0प्र0)

शोधसार–

यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के लिए संदर्भित है, जो मुख्यतः शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत–केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो इसकी परम्परा, संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार में परिवर्तन लाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने को तत्पर है। नई शिक्षा का उद्देश्य बिना किसी भेद–भाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बृद्धि और आत्मविश्वास का सृजन कर उनके दृष्टिकोण का विकास करना है।

मूल शब्द– *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल युग, ज्ञान, शिक्षा।*

प्रस्तावना–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन0ई0पी0 2020) जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 में पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, की जगह

ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। इसका उद्देश्य धर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना सभी को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान में. प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवन ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है।

नई शिक्षा नीति 2020 पांच स्तम्भों पर केन्द्रित है–वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता और जवाबदेही,–निरन्तर सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इसे समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के रूप में नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। जिससे नियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करना, संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 2030 में सूचीबद्ध पूर्ण और उत्पादक रोजगार और अच्छे काम की ओर अग्रसर होना, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य हे। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है और 2040 तक भारत में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों को बदलने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। जिससे वे नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सके। इस प्रकार नई शिक्षा नीति बहु–विषयकता, डिजिटल साक्षरता, समस्या–समाधान, तार्किक और व्यावसायिक प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा–

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (जी0आई0आर0) को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए एन0ई0पी0 2020 की कल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा में प्रौद्योगिक के उपयोग को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करके छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना है।

उसके अलावा देश में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एन0आर0एफ) की स्थापना की जायेगी। देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक के रूप में परिकल्पित एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद की स्थापना की जाएगी। सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एन0टी0ए0) और समान स्तर की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सी0ई0टी0) स्थापित करने के प्रयास किय जाएंगे।

स्कूली शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान–

नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।

एन0ई0पी0 2020 के तहत् बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा–3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जायेगा।

नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कए एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (एच0ई0सी0आई0) की परिकल्पना की गई है। जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान–

इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केन्द्र, आवास, सहायक उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारम्भिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जायेगा।

डिजीटल शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान–

एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक मंच का गठन किया जाएगा। जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान–प्रदान किया जा सकेगा।

डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जायेगा जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

नई शिक्षा नीति से सम्बन्धित चुनौतियां

राज्यों का सहयोग–

शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं, इसलिए इस फैसले के वास्तविक क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने सम्बन्धी विचार का राज्यों द्वारा समर्थन करना होगा।

महंगी शिक्षा–

नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महंगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

शिक्षा का संस्कृतिकरण–

दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रि–भाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।

फंडिंग सम्बन्धी जांच का अपर्याप्त होना–

कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क सम्बन्धी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियांए असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं।

वित्त पोषण–

वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जी0डी0पी0 के प्रस्तावित 6 प्रतिशत खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है।

निष्कर्ष–

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21वी0 सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जायेगी।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा रटने वाले विषयों, समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कही अधिक है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को प्राप्त करना और उस क्षेत्र में निरन्तर कार्य करना और प्रगति करना है। यदि नई शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू किया जाये तो यह भारतीय शिक्षा को नई ऊचांईयों पर ले जा सकती है।

सन्दर्भ सूची

1. https://www.education.gov.in
2. https://en.wikipedia.org/wiki/National Education Policy 2020
3. kumar k.(2005).Quality of Edukation at the Beginning of the 21st Century:Lessons from India.
4. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files.
5. Puri,Natasha(30 August 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India-The Need for Data and Dynamism in the 21st century . SSRN.

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-1, April-2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-April-2023/31

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ.राजेश वर्मा एवं प्रेम चन्द्र वर्मा

for publication of research paper title

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-02, Issue-01, Month April, Year-2023.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com